भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 631

06 फरवरी, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य

631. श्री भागीरथ चौधरीः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2024 तक प्रत्येक किसान की आय दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने किसानों के बीच डेयरी और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए उक्त प्रयोजनार्थ कोई विस्तृत कार्य योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं और उक्त लक्ष्य की प्राप्ति में अब तक क्या प्रगति हुई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि आवंटित की गई है और आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितनी धनराशि आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा)

(क) एवं (ख): सरकार ने "किसानों की आय दोगुनी करने (डीएफआई)" से संबंधित मुद्दों की जांच करने और इसे हासिल करने के लिए कार्यनीतियों की सिफारिश करने हेतु अप्रैल, 2016 में अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया था। समिति ने सितंबर, 2018 में सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी जिसमें विभिन्न नीतियों, सुधारों और कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करने की सिफारिशें शामिल हैं। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, समिति ने आय वृद्धि के निम्नलिखित सात स्रोतों की पहचान की:

i. फसल उत्पादकता में वृद्धि

ii. पशुधन उत्पादकता में वृद्धि

iii. संसाधन उपयोग दक्षता - उत्पादन लागत में कमी

iv. फसलन गहनता में वृद्धि

v. उच्च मूल्य वाली कृषि में विविधीकरण

vi. किसानों की उपज पर लाभकारी मूल्य

vii. अतिरिक्त जनशक्ति का कृषि से गैर-कृषि व्यवसायों में अंतरण

सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के बजट आवंटन में वर्ष 2013-14 के दौरान 27,662.67 करोड़ रुपये (बीई) से वर्ष 2023-24 के दौरान 1,25,035.79 करोड़ रूपये (बीई) की काफी वृद्धि की है।

सरकार के निम्नलिखित प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के लिए संवर्धित बजटीय प्रावधान किए गए हैं। भारत सरकार की विभिन्न योजनाएँ/कार्यक्रम किसानों के उत्पादन, लाभकारी प्रतिफल और आय सहायता में वृद्धि करके किसानों के कल्याण के लिए हैं, जिनमें शामिल हैं:

1. पीएम किसान के माध्यम से किसानों को आय सहायता
2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)
3. कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण
4. उत्पादन लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करना
5. देश में जैविक खेती को बढ़ावा देना
6. प्रति बूंद अधिक फसल
7. सूक्ष्म सिंचाई कोष
8. किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का संवर्धन
9. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)
10. कृषि यंत्रीकरण
11. नमो ड्रोन दीदी
12. किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना
13. राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) विस्तार प्लेटफार्म की स्थापना
14. राष्ट्रीय खाद्य तेल - ऑयल पाम मिशन का शुभारंभ

15. कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ)
16. कृषि उपज लॉजिस्टिक्स में सुधार, किसान रेल की शुरूआत।
17. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) - क्लस्टर विकास कार्यक्रम:
18. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में स्टार्ट-अप इको सिस्टम का सृजन
19. कृषि एवं संबद्ध कृषि वस्तुओं के निर्यात में उपलब्धि

इन योजनाओं के क्रियान्वयन से किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में उल्लेखनीय परिणाम मिले हैं। 'आजादी का अमृत महोत्सव' के हिस्से के रूप में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने एक पुस्तक जारी की है, जिसमें असंख्य सफल किसानों में से ऐसे 75,000 किसानों की सफलता की कहानियां संकलित हैं, जिन्होंने अपनी आय दो गुना से अधिक बढ़ाई है।

(ग) से (ङ): किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा किसानों के लिए डेयरी और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही हैं:

i) पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम
ii) अवसरंचना विकास कोष
iii) सहकारी समितियों के माध्यम से डेयरी (ईएपी)
iv) डेयरी विकास
v) राष्ट्रीय गोकुल मिशन
vi) पशुधन संगणना और आईएसएस
vii) राष्ट्रीय पशुधन मिशन

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उपरोक्त योजनाओं के लिए सरकार द्वारा आवंटित धनराशि 4095.64 करोड़ रुपये और आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रस्तावित धनराशि 4210 करोड़ रुपये है।

*****